SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): By coincidence the Minister is here. I was just wondering how all the Special Mentions relate to his Department.

SHRI A. G. KULKARNI: Whether he is present here or not, he is not expected to reply. It is ony in the wilderness we are making appeals.

Sir, the heading of the news item is: "Son of PM's aide in 'dubious deal' ". The whole point seems to be that a deal has been struck with Ferranti of U.K. for the procurement of, what they call, the micro-processor-based system for the ONGC and the Indian Oil Corporation, and for that purpose, it is stated that Shri Ashok Parthasarthy, who is the Department, has gone out of his way. Sir, I quote just three sentences which will throw some light on this matter:

> "The inquiry was conducted under the order of the PM into the conduct of Parathasarthy who presided over the deal. The report of the committee said that by and large the team lacked professional standing in the area of computers in the area of the hardware and software architect point of view. No computer of communication expert of the Department of Electronics accompanied the team."

This is what it seems Mr. Parathasarthy did on his own. The previous Minister, Mr. C.P.N. Singh, complained to the Prime Minister about this. He has stated like this in the file:

> "seriousness of the case deserves attention and unless serious action is taken, I feel the Government will be embarrassed some day if such lapses come out into the open. Deterrent action would enhance the administrative capability of the Government".

This is what Mr. C.P.N. Singh, the previous Minister, had stated. And the final outcome is that the file has not reached the Prime Minister and the deal has been carried through.

I am only worried, there are two aspects in this. One is the dubious way in which it is handled And the second is that the indigenous technology has been given a go-by by certain people near the Prime Minister's Secretariat, which, if it had been processed properly, as Mr. C.P. N. Singh has stated, could have been avoided. Thereby lakhs and crores of rupees are spent unnecessarily and locked. Sir, I draw your attention to it, with the hope that you will advise the Government to go into this news-item and the mention I made. A reply could be given to me and to the people and to the House as to what has actually happened is correct or not.

REFERENCE TO THE ALLEGED HARMFUL EFFECTS OF EFFLUENT DISCHARGE FROM DYING MILLS IN RAJASTHAN

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, राजस्थान स्टेट के जोधपुर पाली, बगैनतला कस्बों में और आसपास के इलाकों में एक बड़ी विपत्ति आ गई है। वहां पर तीन शहरों में रंगाई की छपाई की करीब करीब 1200 छोटी बड़ी फैक्टरियां काम कर रही है और इनमें करीब 80 हजार मजदूर काम करते है । इन मिलों का जो गन्दा पानी है वह खुली नालियों में बहता है । जोधपुर मेडीकल कालेज की एक टीम ने और जोधपुर विश्व-विद्यालय की एक टीम ने यहां का सर्वेक्षण किया है और इस बात की घोषणा की है कि इस गन्दे पानी का निकास जो हो रहा है वह खुली नालियों में बह रहा है और वहां के मजदूरों में अनेक किस्म की बीमरियां पैदा हो रही हैं । यहां तक केंसर का रोग भी बड़ी

[श्री शांति त्यागी]

तादाद में फैल रहा है । मजदूर बस्तियों में बड़ी परेशानी है और इसके अलावा पशु-पक्षियों पर भी पानी असर अंदाज हो रहा है और बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं । यह भी कहा गया है कि आस-पास के इलाकों में जहां खेतों में काश्त होती है वहां से यह पानी निकलता है तो वहां पर वनस्पति बरबाद हो रही है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मजदूर तबको की सेहत को बचाने के लिए, वनस्पति को बचाने के लिए, पशु-पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए और वहां के किसानों को बचाने के लिए सरकार को इस गन्दे पानी की निकासी और उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिये । इन अल्फाज के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं जो आपने बोलने का मौका दिया । धन्यवाद ।

Reference to the reported closure of Sugar Mills in Bihar

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिये इस सदन का, इस सरकार के कृषि मंत्री का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर खीचना चाहता हूं और वह विषय है बिहार की चीनी मिलें अभी तक खोली नही जा रही हैं इससे वहां के गन्ना उत्पादकों में हाहाकार मचा हुआ है और खेतों मे गन्ना बरबाद हो रहा है लेकिन हैरानी की बात है कि दुर्भाग्य से उन्ही मिलों को खोलने में देरी हो रही है जो मिलें सरकार के कब्जे में हैं यानी सरकार ने जिन को ले लिया है । तीन मिलें, सकर, लोहाट और गयाम आपके उत्तर बिहार में हैं जिनका सरकारीकरण हो गया है लेकिन उनको खोलने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है और यह उन मिल प्रबन्धकों की धांधली की वजह से है । मेरे पास बिहार के अखबार हैं जहां के यह समाचार है । वहां पर बागाह, सीतामढ़ी और बेनीपुर में हर जगह गन्ना उत्पादकों में हाहाकार है । अखबार में से मैं थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं जिससे बात साफ हो जाएगी ।

जनता पार्टी बेनीपुर के अध्यक्ष सरदार ठाकुर ने बताया जब से सरकार द्वारा चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया है तब से मिलों की स्थिति दुखद हो गई है । अभी तक लाखों रुपया मिलों के जिम्मे किसानों का बकाया है । उन्होंने बताया है कि मिलों के महाप्रबन्धक और ईख प्रबन्धक के आपसी मतभेद के कारण गन्ना उत्पादकों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है और मिलों की हालत दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है ।

तो इनमें मिलें खोली नहीं जा रही है । यह चीनी मिलें सरकारी कब्जे में हैं और किसानों का जो बकाया है उसका भी भुगतान नही किया जा रहा है । गन्ने का जो निर्धारित मूल्य है वह भी नही दिया जा रहा है और प्रबन्धकों और संचालकों की आपसी गड़बड़ी की वजह से दुर्व्यवस्था की वजह से मिलें वहां का बन्द है । इसलिए मेरा कहना है कि कृषि मंत्री जी इसमें अविलम्ब हस्तक्षेप करें दखल दें और देखें कि क्यों बिहार की मिलें नहीं खुल रहीं हैं खासकर जिन मिलों पर सरकार का कब्जा है । किसानों का जो बकाया है वह दिलवायें और गन्ने का निर्धारित मूल्य दिलवा और मेनेजमेंट की जो धांधली है उसको भी खत्म करवाए ।